किसानों को दिया जाएगा 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण : दक

विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य की सहकारी समितियों में पारदर्शिता के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। गबन-घोटालों में लिप्त कार्मिकों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही, वर्षों से लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा कर उनका निस्तारण किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए नवीन को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

मंत्री मंगलवार को विधानसभा में विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने सहकारिता विभाग की 18 अरब 48 करोड़ 27 लाख 97 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

दक ने कहा कि सहकारिता के व्यापक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही, भारत के सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने के लिए 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम की शुरूआत की गई है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी का साथ अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारी समितियां बहुउद्देशीय लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। राज्य में विभिन्न प्रकार की 42 हजार 352 सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 करोड़ 34 लाख 90 हजार से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की खाद, बीज, जुताई और अन्य छोटी-छोटी जरूरतों के लिए राज्य सरकार ने ब्याजमुक्त अल्पकालीन ऋण की सीमा बढ़ाकर 25 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। इसके लिए 768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आगामी वित्तीय वर्ष में 2.50 लाख गोपालक परिवारों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है, जिस पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार अधिक से अधिक पशुपालकों को इस योजना से

- **'सहकारी समितियों में पारदर्शिता के लिए उठाये जा रहे प्रभावी कदम नवीन को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की हो रही कार्यवाही'**

लाभान्वित करने का प्रयास करेगी।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की, जिसके तहत देश के लभगग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सालाना 6 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। इसी क्रम में राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत देय राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा की गई है। अब राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को सालाना 9000 रुपये की राशि मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि योजना में कुछ अनियमितताएं भी सामने आई हैं, जिनमें हमारी पारदर्शी सरकार दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेगी।

दक ने कहा कि सहकारिता की पहुंच राज्य के दूर-दराज क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए आगामी 2 वर्षों में शेष रही 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदण्डों का सरलीकरण किया गया है। साथ ही, नवीन 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए भी राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसे मूर्त रूप देने के लिए महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निर्णय किया है और अब तक 54 नवीन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया गया है। इसमें महिला सदस्यों की हिस्सा राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

दक ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में 6781 पैक्स पर कम्प्यूटराइजेशन किया जा चुका है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकत अन्न भण्डारण योजना के तहत राज्य में नए गोदामों का निर्माण प्रगति पर है। राज्य बजट में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 100 एवं 250 मैट्रिक टन क्षमता के 50 नये गोदामों का निर्माण कराये जाने तथा 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण की भी घोषणा की गई है। इससे राज्य की भण्डार क्षमता में 1.13 लाख मैट्रिक टन की वृद्धि होगी।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे कुशल प्रबंधन से किसानों के बीमा प्रीमियम में कमी आई है, जिसका सीधा लाभ किसान भाइयों को हुआ है। वर्ष 2023-24 में किसानों पर डाले गए अतिरिक्त वित्तीय भार की जांच करवाई जा रही है, जिसके बाद संलिप्तता पाए जाने दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 में मूंग, मूंगफली एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर ऐतिहासिक खरीद की है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गत पांच वर्ष में भी इतनी खरीद नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

अवैध जल कनेक्शन हटाने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान : चौधरी

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने गर्मी में सुचारु पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन से अवैध जल कनेक्शन के लिये राज्य में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। चौधरी ने मंगलवार को बताया कि विशेष अभियान के दौरान जल योजनाओं पर अवैध जल कनेक्शन हटाये जाने के साथ ही नियमित किये जाने का अभियान भी जारी रखा जाएगा। इस दौरान फील्ड के अभियंताओं द्वारा नियमित निगरानी करते हुए सघन कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।

जलदाय मंत्री ने बताया कि अवैध जल संबंधों को नियमित नहीं करवाया गया है, तो उन्हें नोटिस जारी किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेघश्याम सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। सिंह ने अध्यक्ष देवनानी को पुष्प गुच्छ भेंट किया। देवनानी को सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में जानकारी भी दी।

शून्यकाल में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

टीकाराम जूली ने सांगानेर में और हरिमोहन शर्मा ने बूंदी जिले में हुई दुष्कर्म और मर्डर की घटना का मामला उठाया

जयपुर। प्रदेश में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर मंगलवार को विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरा और कानून-व्यवस्था फेल होने के आरोप लगाए। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सांगानेर में पुलिसकर्मी द्वारा दुष्कर्म किए जाने और विधायक हरिमोहन शर्मा ने बूंदी जिले में हुई दुष्कर्म और मर्डर की घटना का मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई और हंगामा भी हुआ।

टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक महिला से दुष्कर्म का मामला उठाते हुए कहा कि रक्षक की भक्षक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के इलाके में यह हो रहा है, तो बाकी जगह के हालात क्या होंगे। हालांकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई अमल में लाएगी। वहीं सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते

- **गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मीडिया से बातचीत करते हुए सांगानेर दुष्कर्म मामले में कहा कि आरोपी पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार करके उसे निलंबित कर दिया गया है, जांच चल रही है।**

हुए जूली ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज हुई है? किन लोगों के दखल से दर्ज हुई है? यह बात सब जानते हैं।

कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने के बड़े-बड़े वादे भाजपा ने चुनाव में किए थे। अब भाजपा सरकार में महिलाओं के प्रति संगीन अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का दावा है कि हमारी सरकार में अपराध कम हुए। इसकी वजह यह है कि भाजपा सरकार ने दिसंबर में ही एफआईआर दर्ज करना बंद कर दिया था। जबकि कांग्रेस सरकार में एफआईआर दर्ज होती थी। अब भाजपा सरकार कोशिश कर रही है कि एफआईआर कम से कम हो, इसलिए एफआईआर दर्ज ही नहीं किया जा रहा है।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मीडिया से बातचीत करते हुए सांगानेर दुष्कर्म मामले में कहा कि आरोपी पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार करके उसे निलंबित कर दिया गया है, जांच चल रही है। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अगर कोई कार्मिक इस तरह का घिनौना करते करता है, तो यह चिंतनीय बात है। नियमों में जो भी प्रावधान होंगे, उसके मुताबिक आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कानून-व्यवस्था के मामले में सरकार के फेल होने के आरोप लगाए थे।

गर्भवती महिलाओं को पौष्टिकता के अनुसार दिया जाए सुपोषण न्यूट्री किट : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता और महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के सम्बंध में बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 225-26 की बजट घोषणा के अनुसार गर्भवती महिलाओं को पांचवे महीने से न्यूट्री किट उपलब्ध करवाये जाने हेतु "सुपोषण न्यूट्री किट योजना" को साकार रूप दिए जाने के लिए अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिकता का संवर्धन करने वाले भोज्य पदार्थों को "सुपोषण न्यूट्री किट" में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता से गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोषण युक्त खान-पान किट उपलब्ध करवाने हेतु कार्य कर रही है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में "मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना" के तहत आंगनबाडी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर अब 1 अप्रैल 2025 से पांच दिन दूध उपलब्ध करवाये जाना शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओ पी बुनकर, वित्तीय सलाहकार पदमचंद, अतिरिक्त निदेशक अनुपमा टेलर, उपनिदेशक डॉ. मंजू यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता और महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक बार फिर आवेदन शुरू

जयपुर। केंद्रीय बजट2024- 25 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 21 से 24 वर्ष की आयु के एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह पहल 12 महीने की अवधि के लिए विभिन्न उद्योगों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल से रूबरू कराएगी। इस योजना को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा कैडर के अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय निदेशालय- नॉर्थवेस्टर्न प्रमुख एजेंसी है।

यह योजना 21 से 24 वर्ष की आयु के उन युवाओं को लक्षित करती है जो वर्तमान में किसी भी पूर्णकालिक शैक्षिणक कार्यक्रम या रोजगार में नामांकित नहीं हैं।

किसानों के नाम पर कुछ संगठित गिरोह बन गये हैं, जो किसानों का नाम खराब कर रहे हैं : सारस्वत

सदन में अनुदान मांगों पर बहस में भाग ले रहे थे विधायक

जयपुर। भाजपा विधायक ताराचंद सारस्वत ने अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कहा कि हमारे इलाके में किसानों के नाम पर कुछ संगठित गिरोह बन गए हैं, जो किसानों का नाम खराब कर रहे हैंयह संगठित गिरोह फर्जी गिरदावरी बनवाकर एमएसपी फसल खरीद में गड़बड़ी करता है। किसान 10 दिन तक इंतजार करता रहता है और यह संगठित गिरोह सरकारी खरीद का फायदा उठा लेता है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों से लेकर पूरे सहकारी सिस्टम पर इसी गिरोह ने कब्जा कर रखा है। यह लोग किसानों का नुकसान कर रहे हैं । हम लोग भी किसान का नाम होने के कारण बोल नहीं पाए, क्योंकि हम खुद भी किसान है हम किसान की बदनामी कैसे करें। ऐसे लोगों की पहचान करके उन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। सारस्वत ने कहा कि इस गिरोह का नेटवर्क इफको के हेड क्वार्टर से लेकर सब जगह पर है। इस गिरोह ने हमारे यहां नकली सरसों तक बेच दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सब जगह इसी गिरोह का नेटवर्क है। मैंने इफको के एमडी तक को फोन कर शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ।

कांग्रेस विधायक शिमला देवी नायक ने सहकारिता और खाद्य विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कहा कि किसान को आज भी उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता। किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून नहीं बना। केंद्र में आज तो डबल इंजन की सरकार है, लगभग 700 किसान शहीद हुए थे, आज भी हमारा किसान जगजीत सिंह मरणासन्न है। क्या आप बताना चाहेंगे, एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून कब लेकर आएंगे? किसान की बात तो आप बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। शिमला देवी ने कहा कि एक तरफ तो कहते हैं एमएसपी थी है और रहेगी, लेकिन राजस्थान में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन सरकार क्या इसकी एमएसपी पर खरीद करेगी। 1 अप्रैल से गेहूं की फसल बाजार में आती है, लेकिन इससे पहले सरसों बाजार में आ जाती है। इसकी खरीद की क्या व्यवस्था की। अभी बीच में जो टेंडर था, उसको भी रोक दिया। 15 मार्च तक एमएसपी पर सरसों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया चालू करें, ताकि किसान को ज्यादा लाभ मिल सके। एमएसपी पर खरीद में जन आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड से खरीद का सिस्टम लागू करें।

कांग्रेस सरकार के समय पीएम किसान सम्मान निधि में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े का विषय विधानसभा में गूंजा। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने हजारों अपात्र लोगों को किसान सम्मान निधि का भुगतान किया। उन्होंने मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र का उदहारण दिया, जहां 2019 से 2023 के बीच 13,858 अपात्र लोगों को 8.26 करोड़ रुपए दिए जाने का खुलासा हुआ है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिये 505 सलाहकार समितियां गठित : गोदारा

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए 406 ग्राम एवं तहसील स्तरीय और 99 नगरपालिका स्तरीय आवंटन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।गोदारा ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जयपुर जिले में नई आवंटन सलाहकार समितियों का गठन जल्द ही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 98 उचित मूल्य की दुकानों में से 27 दुकाने अटेच हैं।

- **विधानसभा में विधायक अमीन कागजी ने उठाया मामला**

इससे पहले विधायक अमीन कागज़ी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2024 तक 15 उचित मूल्य की दुकानें निलंबित की गई। यहां तीन उचित मूल्य की दुकानें त्यागपत्र, दो मृत्यु और सात निरस्त होने की वजह से रिक्त है, उन्होंने निलंबित दुकानों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशनकार्डो अथवा दो हजार यूनिट पर नवीन उचित मूल्य की दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के गठन उपरान्त किशनपोल में रिक्त उचित मूल्य दुकानों का यथाशीघ्र आवंटन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र किशनपोल में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2024 के बीच कोई उचित मूल्य दुकान स्वीकृत नहीं की गई।

पर्ची सरकार सदन से सड़क तक फेल : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र का ढोल पीटने वाली सरकार मंत्रियों की सदन में फजीहत से निराश मुख्यमंत्री 20 मिनट में ही सदन से बाहर निकल गये। यदि पूरे प्रश्नकाल में सदन में बैठते तो सच्चाई का पता चल जाता है। जूली द्वारा श्रम विभाग से सम्बन्धित पूछे गये प्रश्न का जवाब देते समय सरकार की कलई खुल गई। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से जो भी वादे किये गये उनमें से एक भी इंप्लीमेंट नहीं किया।

जूली ने बताया कि उनके द्वारा जब यह पूछा गया कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं तो मंत्री इसका जवाब तक नहीं दे पाए।

आरोपियों के परिजनों की संपत्ति तोड़ने पर यथास्थिति जारी

जयपुर। हाईकोर्ट ने अजमेर के बिजयनगर ब्लैकमेल कांड के पांच आरोपियों के परिजनों की संपत्ति तोड़ने के जारी नोटिस पर दिए गए यथा-स्थिति आदेश को 24 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिकाकर्ता को उस पर अपना प्रति-जवाब देने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश शाकीर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने जवाब पेश किया। राज्य सरकार ने अपने जवाब में याचिका को लेकर आपत्तियां पेश की हैं। जवाब में कहा गया कि स्थानीय निकाय ने हर याचिकाकर्ता को अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं। ऐसे में संयुक्त याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तथ्य छिपाकर याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर संबंधित संपत्ति के दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया,

- **राज्य सरकार ने पेश की आपत्तियां**

लेकिन उन्होंने दो दिन बाद ही याचिका पेश कर दी। इसके अलावा सिर्फ नोटिस देने की कार्रवाई को याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि नोटिस के बाद स्थानीय निकाय कोई कार्रवाई करता तो उसे भी नगर पालिका अधिनियम के तहत हाईकोर्ट के बजाए अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देने होती है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने यथा-स्थिति को जारी रखते हुए याचिकाकर्ता को 24 मार्च तक अपना प्रति-जवाब देने को कहा है।

याचिका में सैयद सआदत अली ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के घर के युवाओं को पुलिस ने कथित रूप से हुए ब्लैकमेल कांड में फंसाया है। अभी सभी आरोपी गिरफ्तार व न्यायिक अभिरक्षा में हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के घर नोटिस चस्पा कर कब्जा हटाने की चेतावनी दी है।

पतंजलि फूड पार्क की स्थापना से विदर्भ के किसान को अब नहीं होना पड़ेगा आत्महत्या के लिए बाध्य : गडकरी

राष्ट्रीय/नागपुर। पतंजलि द्वारा मिहान, नागपुर में स्थापित संतरा प्रोसेसिंग के एशिया के सबसे बड़े प्लांट 'पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क' का विधिवत उद्घाटन सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने किया।

हिन्दवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए फडणवीस ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन नितिन गडकरी, स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने प्रदेश में पतंजलि के सेवा विस्तार का जो सपना देखा था वह अब भव्य रूप से साकार हो रहा है। इसकी स्थापना में अनेक बाधाएँ व विघ्न आए लेकिन स्वामी का संकल्प था कि चाहे जितनी भी बाधाएँ आएँ हम यह संकल्प पूर्ण करके रहेंगे और आज वह संकल्प पूर्ण हो रहा है। पतंजलि का उद्देश्य यहाँ के किसानों की समृद्धि है। उन्होंने बताया कि आचार्य जी से वार्ता के अनुसार क्षेत्र के सारे संतरों का केन्द्र भी यही फूड पार्क बनेगा। उद्घाटन अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि मैं सर्वप्रथम स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को धन्यवाद दूंगा कि मेरे और देवेन्द्रजी के आग्रह पर उन्होंने मिहान, नागपुर में फलों का प्रसंस्करण करने वाले उद्योग की शुरूआत की। स्वामी रामदेव जी ने जो इनिशियेटिव लिया है,वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क,मिहान में बेहतर तकनीक को लाकर स्वामी जी ने किसानों को राहत तथा युवाओं को रोजगार देने का सराहनीय कार्य किया है। उनके सहयोग और उदार दृष्टिकोण से समाज में शोषित पीड़ितों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मिहान, नागपुर में स्थापित संतरा प्रोसेसिंग के एशिया के सबसे बड़े प्लांट 'पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क' का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे।

- **देश की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट "पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क" मिहान,नागपुर का लोकार्पण**
- **नागपुर से पूरे देश व दुनिया को पेस्टीसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स तथा शुगर रहित 100 प्रतिशत संतरे का जूस होगा उपलब्ध : स्वामी रामदेव**
- **यह यूनिट संतरा उत्पादन करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगी : देवेन्द्र फडणवीस**

इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि नागपुर देश का एक आदर्श महानगर ही नहीं अपितु धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, औद्योगिक, सुरक्षा, समृद्धि तथा वैल्थ क्रिएशन की दृष्टि से एक अप्रतिम स्थान है। यहाँ पर राजनैतिक दृष्टि से दो-दो राष्ट्रीय नेतृत्व, दिव्य चरित्र से युक्त आदर्श व्यक्तित्व देवेन्द्र फडणवीस तथा नितिन गडकरी जी हैं। स्वामी जी ने कहा कि पतंजलि द्वारा नागपुर में एशिया का सबसे बड़ा संतरा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है जिसमें लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है तथा अभी 500 करोड़ और निवेश की योजना है। इस प्लांट में देश-विदेश से उच्च तकनीक युक्त मशीनें लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि संतरे का जूस सबसे बड़ा एंटी एजिंग होता है,इसे पीने से लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते।

कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क का जो मूर्त रूप दिखाई पड़ रहा है इसमें तीन महापुरुषों का अभुतपूर्व योगदान है। इस कार्य में स्वामी महाराज की दूरदृष्टि, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की महाराष्ट्र को लेकर संवेदना तथा कार्य करने की भावना और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु नितिन गडकरी की विदर्भ के किसानों के लिए तड़प और ललक निहित है।